

मध्यान्ह भोजन में मलिट्स को शामिल करने के मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को भारत सरकार ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

18 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में मलिट्स को शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र की मंजूरी के पश्चात् अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर सप्ताह में चार दिन स्कूली बच्चों को मलिट्स से निर्मित खाद्य पदार्थ वितरित किये जाएंगे।
- वदिति है कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप लोक शक्ति संचालनालय ने केंद्र सरकार को इस योजना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सोया चिक्की के स्थान पर मलिट्स से बने खाद्य सामग्री वितरित किये जाने का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के डायरेक्टर, पीएम पोषण द्वारा मंजूरी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में मलिट्स के उत्पादन के लिये किसानों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोदो, कुटकी-रागी जैसे मलिट का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा रहा है। इसके अलावा मलिट मशिन के अंतर्गत राज्य के मलिट्स उत्पादक किसानों को 9 हजार रुपए की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मलिट वर्ष घोषित किया गया है।
- गौरतलब है कि पूर्व में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की वार्षिक कार्ययोजना में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में बच्चों को पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 55 दिनों के लिये सोया चिक्की प्रदान करने के लिये केंद्रांश के रूप में 1787.20 लाख रुपए और राज्यांश के रूप में 1198.14 लाख रुपए इस प्रकार कुल 2995.34 लाख रुपए की मंजूरी दी गई थी।